ACHIEVER IAS ACADEMY

SUMMARY OF THE HINDU

HINDI

TALK TO US

+918434931877, +917250667974

achieveriaspatna@gmail.com

www.achieveriaspatna.co.in

NEW PATLIPUTRA COLONY ROAD NO. 4A, NEAR TENNIS COURT, PATNA-13

द हिन्दू 02-05-23

राष्ट्रीय

न्यायिक पैनल मणिपुर हिंसा की जांच करेगा

केंद्रीय गृह मंत्री ने गुरुवार को कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे और हिंसा के "कारणों" का पता लगाएंगे और "जिम्मेदारी तय करेंगे"।

गृह मंत्री ने हाल की हिंसा को "जातीय हिंसा" करार दिया। उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई दर्ज किए गए सभी मामलों की अपनी जांच करेगी। सीबीआई पांच का चयन करेगी और कंपेयर का एक सामान्य मामला दर्ज करेगी।

उग्रवादियों को चेतावनी

उन्होंने कुकी उग्रवादी समूह को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। यदि ऑपरेशन के निलंबन (एसओओ) की शर्तों का उल्लंघन किया गया था।

SoO - यह सरकार के बीच 2008 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और कुकी छाता निकाय 'द यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट' और 'कूकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन' जो संयुक्त रूप से 24 विद्रोही समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसमें 2,200 सशस्त्र कैडर थे जिनके हथियारों को SoO के अनुसार सरेंडर करना था।

हालाँकि, यह आरोप लगाया गया है कि कुकी समूह ने हाल की हिंसा में हथियारों का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने पुलिस से लगभग 1420 हथियार लूटने वाले "आरांबाई तेंगगोल" और "मीती लेपन" के सदस्यों से इसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। बता रहे हैं कि सरेंडर नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने हालिया हिंसा के लिए मणिपुर, हे के फैसले को जिम्मेदार ठहराया

जीएसटी संग्रह पांचवीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार, मई में 11.5% तक।

मई में जीएसटी संग्रह 11.5% बढ़ा और 1.57 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया।

घरेलू लेन-देन से राजस्व 11% और आयात एक साल पहले की तुलना में 12% अधिक कर देता है।

डब्ल्यूएफआई प्रमुख के खिलाफ पहलवानों के विरोध को "कैरी फॉरवर्ड" करने के लिए किसान नेता, राष्ट्रपति से मिले।

हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान नेता गुरुवार को महापंचायत के लिए एकत्र हुए और राष्ट्रपति दुउपदी मुर्मू से मिलने का फैसला किया। बैठक भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नरेश टिकैत ने बुलाई थी।

भारत नेपाल ने ऊर्जा परिवहन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए।

नेपाल के पीएम पुष्पा कुमार दहल 'प्रचंड' 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और भारतीय क्षेत्र के माध्यम से बांग्लादेश को नेपाल की जलविद्युत पर निर्यात सहित ऊर्जा और परिवहन पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

परिवहन संबंधी करार :-

• भारत में बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक कार्गो ट्रेन का उद्घाटन किया गया।

• नेपाल में नेपालगंज और भारत की ओर रुपैडीहा में एकीकृत चेकपास्ट (आईसीपी)। यह दो देशों के बीच संचार के लिए एक नया मार्ग खोलेगा।

बिजली से जुड़े समझौते :-

• एक दीर्घकालिक बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके तहत भारत ने आने वाले वर्षों में नेपाल से 10,000 एचडब्ल्यू बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है।

• नेपाल में सिलीगुड़ी से झापा तक नई पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा।

• फुकोट करनाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एनएचपीसी और वीयूसीएल (विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड) नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

• लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के लिए एसजेवीएनएल और निवेश बोर्ड नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन।

• गोरखपुर-भुटावल ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी।

⍰ भारत और चीन ने नई दिल्ली में एलएसी मुद्दे पर बातचीत की।

बुधवार को आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों (डब्ल्यूएमसीसी) पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र की 27वीं बैठक में धीमी गति से चलने वाली वार्ता में कोई प्रमुख प्रगति नहीं होने का सुझाव दिया गया। पिछली बार नई दिल्ली ने जनवरी 2019 को 13वें दौर की डब्ल्यूएमसीसी वार्ता की मेजबानी की थी।

MEA के एक बयान में कहा गया है, "दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ स्थिति की समीक्षा की और फ्रैंक और खुले तरीके से शेष क्षेत्रों में विस्थापन के प्रस्ताव पर चर्चा की।"

चीनी विदेश मंत्रालय के बयान में शेष संबंधों से सीमा को अलग करने की मांग की गई है; एक स्टैंड जिसे भारत ने खारिज कर दिया है।

▯ राजद्रोह कानून बरकरार रखा जा सकता है लेकिन सुरक्षा उपायों के साथ: विधि आयोग

सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में अपने अस्थाई आदेश में IPC 124A के मामले पर रोक लगा दी, जो देशद्रोह से संबंधित कानूनों से संबंधित है। सरकार ने इसकी जांच के लिए विधि आयोग का गठन किया था

IPC 124 A - 1860 में अधिनियमित। जो कोई भी, शब्दों द्वारा, या तो बोले गए या लिखित, या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व द्वारा, या अन्यथा, घृणा या अवमानना करता है या उत्तेजित करता है या सरकार के प्रति असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। भारत में कानून द्वारा स्थापित जुर्माना और कारावास से दंडित किया जाएगा।

क्या कहती है लॉ कमीशन की रिपोर्ट

राजद्रोह से निपटने वाली आईपीसी की धारा 124 ए को बरकरार रखने की जरूरत है, लेकिन इसके वेतन के संबंध में अधिक स्पष्टता के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं।

आयोग ने कहा कि राजद्रोह का "औपनिवेशिक विरासत" होना इसकी पुनरावृत्ति के लिए एक वैध आधार नहीं है, लेकिन धारा 124 ए के दुरुपयोग को देखते हुए, पैनल ने सिफारिश की है कि केंद्र किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी करभारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2030 तक नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होने वाली अपनी आधी स्थापित बिजली के लिए प्रतिबद्ध किया है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने बुधवार को बताया कि 2026-27 की शुरुआत में लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

अप्रैल 2023 अक्षय ऊर्जा से बिजली - 42.5%

2026-27 नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन आदि) से अपेक्षित बिजली - 57.4%

2031-32 अपेक्षित नवीकरणीय बिजली - 68.4%

हटा दिया है।▯ एनसीईआरटी ने 'रेशनलाइजेशन' मूव में सी क्लास एक्स बुक से पीरियोडिक टेबल चैप्टर को

पाठ्यक्रम को कम करने के लिए 9 'तर्कसंगत' अभ्यास आयोजित करने में एनसीईआरटी।

आवर्त सारणी अभी भी ग्यारहवीं कक्षा में बरकरार रहेगी।

दुनिया

▯ पुतिन के खिलाफ आईसीसी वारंट पर दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। ब्रिक्स देशों के प्रमुख अगस्त में डरबन (दक्षिण अफ्रीका) में मिलेंगे।

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोस्ट (ICC) ने मार्च में श्री पुतिन पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया, यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले क्षेत्र से बच्चों को जबरन रूस भेज दिया।

दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का सदस्य है। और सैद्धांतिक रूप से इसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तब गिरफ्तार करना होगा जब वे डरबन में ब्रिक्स के दौरे पर जाएंगे।

इन सवालों का जवाब देते हुए दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री नलदेई पंडोर ने कहा, "हमारी सरकार इस समय देख रही है कि इस मामले में हमारे पास क्या विकल्प हैं"। उत्तर यह है कि राष्ट्रपति इंगित करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका की अंतिम स्थिति क्या है

फिलहाल ब्रिक्स के लिए आमंत्रण सभी सदस्य देशों को भेज दिया गया है। क्रेमलिन ने बताया है कि रूस उचित स्तर पर हिस्सा लेगा।

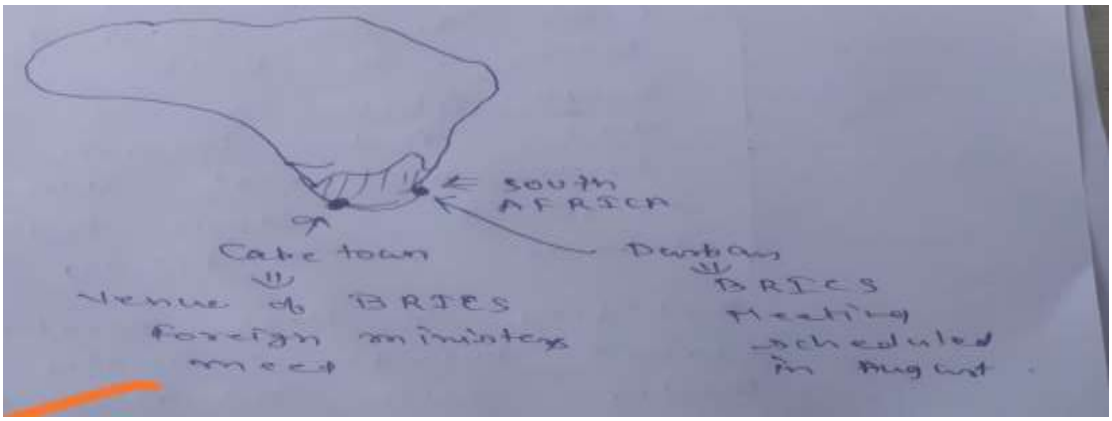

? अमेरिका और ताइवान ने व्यापार समझौता किया क्योंकि चीन ने चेतावनी जारी की।

अमेरिका और ताइवान ने गुरुवार को एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, गुरुवार को दोनों पक्षों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने बीजिंग को चेतावनी दी है।

21वीं सदी में अमेरिका-ताइवान की पहल सीमा शुल्क को सुव्यवस्थित करके, नियामक प्रक्रियाओं में सुधार करके और अमेरिका और ताइवान के बीच भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की स्थापना करके व्यापार को बढ़ावा देती है।

चीन ने गुरुवार को चीन को ऐसे किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर करने की चेतावनी दी। इसने कहा कि अमेरिका को "व्यापार के नाम पर ताइवान की स्वतंत्र सेना को गलत संकेत नहीं देना चाहिए"।

चीन ताइवान को अपना क्षेत्र कहता है। अमेरिका और ताइवान के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है लेकिन वे अनौपचारिक संबंध बनाए रखते हैं। ताइपे में "ताइवान का अमेरिका संस्थान"।

? उत्तरी कोसोवो में सर्बों की रैली के रूप में अमेरिका ने राजनयिक दबाव डाला।

कोसोवो में तनाव क्यों उभरा?

जातीय अल्बानियाई और सर्बियाई के बीच संघर्ष तब सामने आया था जब मिट्रोविका के सर्बियाई बहुल क्षेत्र में एक अबानियन को मेयर चुना गया था।

जातीय सर्ब इसका विरोध कर रहे हैं वे नाटो के नेतृत्व वाले पीसकीपर फोर्स (केएफओआर) के साथ भी भिड़ गए हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने गुरुवार को प्रिस्टिना और बेलग्रेड दोनों से तनाव कम करने का आग्रह किया।

मित्रोविका में सर्बियाई के साथ संघर्ष में दो अल्बानियाई घायल हो गए।

कोसोवो - 92% अल्बानियाई 4% सर्ब कोसोवो फरवरी 2008 को सर्बिया का हिस्सा था, कोसोवो ने एकतरफा खुद को सर्बिया से स्वतंत्र घोषित कर दिया।

कोसोवो द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा करने का एक मुख्य कारण यह था कि इस क्षेत्र में अल्बानियाई लोगों का प्रभुत्व था।

संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 101 संयुक्त राष्ट्र के देश KOSOVO को संप्रभुता के रूप में मान्यता देते हैं, रूस, सर्बिया और कई अन्य राष्ट्र KOSOVO को मान्यता नहीं देते हैं।

कोसोवो की आबादी - लगभग 18 लाख (2022)

राजधानी – प्रिस्टिना

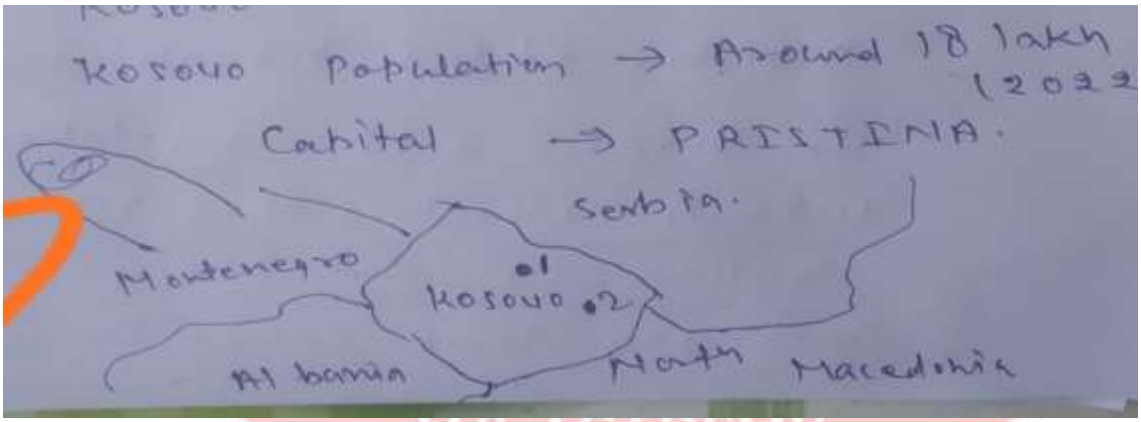

IAS ACADEMY

1 - मित्रोविका (सर्ब का बोलबाला)

2 – प्रिस्टिना (राजधानी)

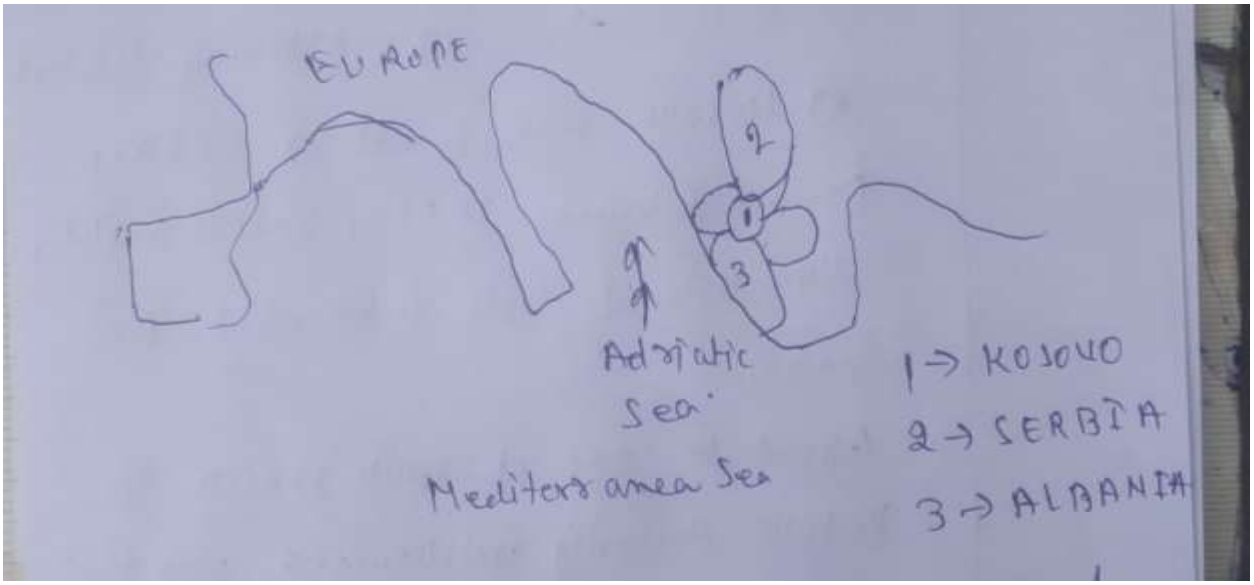

⍰ पाकिस्तान ने लगातार दूसरे महीने रिकॉर्ड बनाया।

मई में पाकिस्तान की मुद्रास्फीति की दर 37.97% बढ़ी और एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया।

अप्रैल में यह था - 36.5%

पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो ने गुरुवार को कहा कि ब्यूरो ने कहा कि सब्जियों, दालों, गेहूं, गेहूं का आटा, चावल, अंडे और चिकन में खाद्य पदार्थ और ईंधन और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है।

⍰ अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने बैठक के लिए चीन के इनकार पर अफसोस जताया।

अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने गुरुवार को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके चीनी समकक्ष सिंगापुर में आगामी सुरक्षा सम्मेलन में उनसे मिलने से इनकार कर रहे हैं।

शांगरी-ला - वार्षिक सुरक्षा वार्ता सिंगापुर में आयोजित की जाती है।

यह भारत में रायसीना संवाद, यूरोपीय संघ में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के समान है।

⍰ अमेरिका ने सूडान के प्रतिद्वंद्वी गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि युद्धविराम विफल हो गया।

अमेरिका ने सूडानी नेताओं पर आर्थिक और वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की।

ACHIEVERS IAS ACADEMY

पाठ / संदर्भ

विज्ञान

? दुनिया के लिथियम का मालिक कौन होना चाहिए?

लिथियम का महत्व

लिथियम आयन बैटरी बनाने में लिथियम का उपयोग किया जाता है। ये बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चलाती हैं; सभी गैजेट जैसे मोबाइल फोन, और अन्य जो बैटरी से चलते हैं जो बिजली से चार्ज होते हैं, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग करते हैं।

शून्य कार्बन उत्सर्जन में परिवर्तन के वैश्विक दबाव ने वाहनों और अन्य उपकरणों में लिथियम आयन के उपयोग की आवश्यकता को बढ़ा दिया है।

भारत का लिथियम रिजर्व

हाल ही में भारत को जम्मू-कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है

पहले भारत लीथियम बैटरियों का आयात करता था। 2019-2020 में, इसने 6600 करोड़ रुपये मूल्य की 450 मिलियन यूनिट लिथियम बैटरी का आयात किया था।

भारत में इन खनिजों का स्वामित्व सरकार के पास है। केवल।

दुनिया भर में लिथियम भंडार के बारे में

चिली, बोलीवा में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार है।

? वीजा पर अमेरिकी धमकी पर ढाका ने कैसे प्रतिक्रिया दी है?

24 मई को, अमेरिका ने एक "नई वीजा नीति" की घोषणा की, जो अमेरिका को बांग्लादेश में व्यक्तियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों पर वीजा प्रतिबंध लगाने में मदद करेगी, जो बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकते है

अमेरिका बांग्लादेश का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। नसीना सरकार। यूएस बांग्लादेश के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखा है यूक्रेन संकट में तटस्थ रुख बनाए रखा है।